ments, productive assets, insurance cover and civic amenities like primary school, well, hand pump, roads tree platforms, transit sheds, dispensaries, seed stores, panchayat ghar etc. as per the respective resettlement and rehabilitation packages of the concerned states.

मेरठ (उत्तर प्रदेश) के लिए सिंचाई परियोजनाएं

803. **श्री सोमपाल :**
श्री राधा किशन मालवीय :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेरठ जनपद में रजपुरा और बिनौला विकास खंडों में भूमिगत जल स्तर में भारी गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों नलकूप बेकार हो गए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सरकार तथा केंद्रीय जल आयोग के अनुमोदनार्थ कोई सिंचाई योजना/प्रस्ताव भेजा है ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उन पर केंद्रीय सरकार तथा केंद्रीय जल आयोग की प्रतिक्रिया क्या है ;

(घ) क्या इस क्षेत्र की उक्त विकराल समस्या के निदान हेतु कोई वैकल्पिक योजना केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेरठ जिले के रजपुरा और बिनौली के डार्क ब्लाकों में भूजल स्तर में गिरावट आई है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने 29.81 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक परियोजना रिपोर्ट मार्च, 1993 में केंद्रीय सरकार जल आयोग के विचार के लिए प्रस्तुत की है जिसमें हिंडन-कृष्णी दोआब में खरीफ चैनलों के निर्माण की परिकल्पना है। इस परियोजना में भूजल संतुलन को पुनः स्थापित करने तथा मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में हिंडन-कृष्णी दोआब में लगभग 33,900 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत सिंचाई नहर प्रणाली की व्यवस्था करके जल स्तर में गिरावट को रोकने की भी परिकल्पना है। केन्द्रीय जल आयोग में इस परियोजना का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने देश में नाजुक ब्लाकों में भूजल पुनर्भरण की एक स्कीम तैयार की है।

मध्य प्रदेश में कमान क्षेत्र विकास योजना

804. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की किन-किन परियोजनाओं में कमान क्षेत्र विकास योजना चलायी जा रही है ;

(ख) रानी अवन्ती बाई सागर (बरती) परियोजना कमान क्षेत्र में उक्त योजना कब से प्रारंभ की जाएगी ; और

(ग) अभी तक इस परियोजना क्षेत्र में यह योजना प्रारंभ न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) (क) मध्य प्रदेश, जहां कमान क्षेत्र विकास स्कीम लागू है, में परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। (नीचे देखिये)

(ख) रानी अवन्ति बाई सागर (बारगी) परियोजना को वर्ष 1990-91 के दौरान केंद्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पहले ही शामिल किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।